आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 07.01.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने 2025–26 की बजट घोषणा के अनुसार सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजना के लिए 17 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव–वन्यजीव संघर्ष की बढती घटनाओं के नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
- अल्मोड़ा में जल निकायों और नौलों–धारों की संगणना के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।
- सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व जन–जागरूकता के उद्देश्य से हरिद्वार में गंगा सभा ने दिलाई शपथ।

परियोजनाएं

आर्थिक कार्य विभाग ने केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई घोषणा पर अमल के लिए तीन वर्षीय सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन तैयार की है। इसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र–शासित प्रदेशों की आठ सौ 52 परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी कुल लागत 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि पाइपलाइन में सार्वजनिक–निजी भागीदारी वाली संभावित परियोजनाओं की शुरुआती जानकारी दी जाती है। इससे निवेशकों, विकासकर्ताओं और अन्य पक्षों के लिए बेहतर योजना और निवेश का निर्णय लेना आसान हो जाता ळें

मुख्यमंत्री बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव–वन्यजीव संघर्ष की बढती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित ग्रामों में सोलर फेंसिंग, बायो–फेंसिंग, हनी–बी फेंसिंग, वॉच टावर और अन्य सुरक्षात्मक उपाय अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्कता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों के आयोजन और रैपिड रिस्पॉन्स टीम को निरंतर सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वन्यजीव समन्वय समिति को सक्रिय बनाए रखने के साथ ही संवेदनशील जिलों, ब्लॉकों और ग्रामों की हॉट स्पॉट मैपिंग तत्काल पूरी की जाए। उन्होंने स्कूलों, आंगनबाड़ियों, जलस्रोतों और पैदल मार्गों के आसपास सुरक्षा प्रबंध मजबूत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि भालू और अन्य वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित न हों। श्री धामी ने कहा कि ईको–टूरिज्म व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए आरक्षित वन के अलावा प्रदेश के वन्यजीव अभराण्य और संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों में भी कार्य किये जाएं।

बैठक में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित नौ प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों की 10 किलोमीटर परिधि में उपखनिज चुगान से जुड़े 22 प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ संदर्भित किए जाने का निर्णय भी लिया गया।

आकांक्षी जिला सम्मान

नीति आयोग ने देश के ग्रामीण इलाकों के विकास और ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़ने तथा किसानों की आय दोगुना करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें हरिद्वार जिले को देश में पहला स्थान मिला है, जिसके लिए नीति आयोग द्वारा जिले के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र को सम्मानित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया नीति आयोग द्वारा 2018 में आकांक्षी जिले के रूप में हरिद्वार का चयन किया गया था। इसमें विकास के विभिन्न मानक तय किए गए थे। उन्होंने कहा कि बहादराबाद ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चुना गया था। उन्होंने कहा कि यह एक सतत विकास की प्रक्रिया है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

आगजनी

उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील के ग्राम गुराड़ी में आज तड़के करीब पांच बजे आग लगने से तीन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग, अग्निशमन, एसडीआरएफ, पुलिस, पशु चिकित्सा विभाग और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं तथा स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड में कई मवेशी मारे गए। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राजस्व विभाग ने प्रभावित प्रत्येक परिवार को कंबल, तिरपाल और पांच हजार रुपए की सहायता दी है।

जल निकाय संगणना

अल्मोड़ा में जल निकायों और नौलों–धारों की संगणना के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। सातवीं लघु सिंचाई संगणना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाएं, जल स्रोतों और नौलों–धारों की संगणना को भी शामिल किया गया है। कार्यशाला में सूख रहे जल स्रोतों, नौलों– धारों और तालाबों के संरक्षण पर चर्चा की गई। लघु सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के तहत जल संरक्षण संवर्धन के लिए संगणना का कार्य मोबाईल एप पर आधारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, ताकि डेटा की सतर्कता और प्रदर्शिता सुनिश्चित हो सके। जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार पंत ने कहा कि जल प्रबंधन पर संगणना होना आवश्यक है। इसके आधार पर जल स्रोतों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, ताकि जल की समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सके।

सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व जन–जागरूकता के उद्देश्य से हरिद्वार में गंगा सभा की ओर से सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई। शपथ के माध्यम से आमजन को यह संकल्प दिलाया गया कि वे यातायात नियमों का पालन करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा से जुड़ा सामाजिक दायित्व है। कार्यक्रम में परिवहन विभाग की ओर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा और अन्य अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए सड़क सुरक्षा माह के महत्व पर प्रकाश डाला तथा नागरिकों से यातायात नियमों के पालन में सक्रिय सहयोग की अपील की।

जल जीवन मिशन

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जल जीवन मिशन की स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को दूसरे चरण की योजनाओं के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के कार्मिकों को गांवों में किए जा रहे हर घर जल सर्वेक्षण कार्यो को शीघ्र पूरा कर तय समय में वास्तविक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत आ रहीं शिकायतों और समस्याओं का तत्काल निस्तारण करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने वन क्षेत्र के तहत लंबित योजनाओं को वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय करते हुए शीघ्र निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन और जल स्रोतों के सुधारीकरण के लिए दूसरे चरण में जिले में 571 योजनाओं में से 472 पूरी कर ली गई हैं और शेष पर कार्य चल रहा है।